बिक्रय इस्पात की क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादन

सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने (लाख टन)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र		गैर सरकारी क्षेत्र	
	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन	क्षमता
1983–84	47.7	72.0	16.3	15.0
1984–85	52.8	72.0	17.1	17.4
1985–86	60.0	72.0	17.7	17.4

वर्ष 1983–84, 1984–85 तथा 1985–86 के दौरान लघु इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन क्रमश: 24, 23 तथा 29 लख टन था ।

(ख) वर्ष 1986–87 के दौरान क्षमता उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी वर्ष की समाप्ति पर हो मिलेगी ।

(ग) वर्ष 1987–88 के दौरान लगभग 122.4 लाख टन बिक्रय इस्पात का उत्पादन करने की योजना है जिसमें मुख्य उत्पादकों का हिस्सा 91.4 लाख टन का होगा ।

इस्पात की मांग और उपलब्धता के मध्य अन्तर

2880. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात की मांग तथा उपलब्धता के मध्य कितना अन्तर रहा है ;

(ख) इस सम्बन्ध में चालू वर्ष के दौरान कितना अन्तर रहने की सम्भावना है ; और

(ग) आगामी वर्ष के दौरान इसकी मांग के अनुरूप इस्पात की यथोचित मात्रा उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) वर्ष 1983–84 और बाद के वर्षों में देश में देशी तैयार इस्पात की अनुमानित आवश्यकता/मांग तथा उपलब्धता का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :–

(लाख टनों में)

वर्ष	अनुमानित आवश्यकता/ मांग	देशी उपलब्धता	अंतराल
1983–84	99.2	85.7	(–) 13.5
1984–85	90.1	88.6	(–) 1.5
1985–86	113.5	104.5	(–) 9.0
1986–87	116.2	106.9 (अनुमानित)	(–) 9.3
1987–88 (योजनाएं)	125.9	120.7	(–) 5.2

आगामी वर्ष के दौरान मांग को पूरा करने के लिये किये जा रहे उपायों में ये उपाय सम्मिलित हैं--क्षमता के बेहतर उपयोग के द्वारा इस्पात के देशी उत्पादन में वृद्धि करना, वर्तमान इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन करना, वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना, इस्पात निर्माण की नई क्षमता स्थापित करना और मांग के अधिक अनुरूप प्रॉडक्ट-मिक्स का अधिक सुन्दर ढंग से पुनर्निर्धारण करना। आयात करने की अनुमति उसी स्थिति में दी जायेगी, जहां देशी उत्पादन से मांग को पूरा करना सम्भव नहीं होगा।

इन्दिरा आवास योजना के अधीन आवासीय एककों का निर्माण

2881. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये प्रस्तावित आवासीय एककों की उनकी लागत सहित संख्या क्या है;

(ख) अब तक कितने आवासीय एककों का निर्माण किया गया है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि की शेष अवधि के दौरान कितने एकक का निर्माण किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव): (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना के अधीन आवासीय एककों की संख्या राज्यों द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना के लिये निर्धारित आवंटनों के अनुसार वर्ष दर वर्ष के आधार पर तय की जाती है। 1985-86 और 1986-87 के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में जितने आवासीय एककों की योजना बनाई गई और जिनका निर्माण किया गया, उनको एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट CXLI, अनुबंध सं० 127)

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के शेष वर्षों के दौरान निर्माण किये जाने वाले एककों की संख्या अवधि के दौरान निर्धारित आवंटनों के अनुसार निश्चित की जाएगी।

Buffer stock of pulses

2882. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to create a buffer stock of pulses; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) No, Sir. The Government of India have no proposal to create a buffer stock of pulses.

(b) Question does not arise.

Mica Mining

2883 SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that mica mining industry is facing crisis due to non-reinvestment by the private mine owners; and

(b) if so, the steps Government are taking to help the industry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES IN THE DEPARTMENT OF MINES (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) and (b) Mica mining is facing problems due to the exhaustion of the operating mines whose production has come down. Under the circumstances, private financial